राजेश बिंडल जे. के समक्ष

राधे श्याम - याचिकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाताओ

सी.डब्लू.पी. 2015 का संख्या 61

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 - नियम 19(2) - सेवा से बर्खास्तगी - फर्जी प्रमाण पत्र - याचिकाकर्ता एसएस मास्टर के रूप में सेवा में शामिल हुआ - उसने एमए की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया और प्राप्त किया इसके आधार पर पदोन्नति - चूँकि उक्त डिग्री फर्जी पाई गई तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया - याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी को चुनौती दी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना की क्योंकि समान स्थिति वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया - माना गया कि याचिकाकर्ता एक शिक्षक था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श था - यदि उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी और उसके बाद उसे यह अनुरोध करने की अनुमति दी गई थी कि उसके प्रति उदारता दिखाई जाए, इससे सभी संबंधितों को गलत संकेत जाएगा - शिक्षकों की योग्यता और चरित्र सर्वोपरि है - याचिकाकर्ता ने पहले ही फर्जी डिग्री के आधार पर प्रक्रिया में देरी का अनुचित लाभ उठाया था क्योंकि वह अपनी बर्खास्तगी तक सेवा में बने रहे - अनिवार्य सेवानिवृत्ति उचित सज़ा नहीं होगी क्योंकि पहले से ही प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर वह पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है - वह सेवा से बर्खास्त होने का हकदार था - उपरोक्त जैसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सामान्य निर्देश दिए गए।

अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता बर्खास्तगी की सजा का हकदार है सेवा। वह एक शिक्षक थे, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श थे। यदि उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, जहां पदोन्नति पाने के लिए उसे फर्जी डिग्री पेश करने की अनुमति दी जा सकती है और पदोन्नति पाने के बाद उसे यह अनुरोध करने की अनुमति दी जाती है कि उसके प्रति उदारता दिखाई जाए। इससे सभी संबंधितों को गलत संकेत जाएगा। हमें बुराई को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि सभी के लिए निवारक के रूप में काम किया जा सके। अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया है। अतिरिक्त राशि की वसूली ऐसे व्यक्ति द्वारा फर्जी डिग्री के आधार पर निकाली गई डिग्री भी ऐसे मामलों में अधिकारियों द्वारा जांच की जाने वाली बात है।

याचिकाकर्ता किस तरह का शिक्षक था या हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह खुद फर्जी डिग्री हासिल करने में संलिप्त था। सेवा में और एक ही समय में प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाना। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं और एक शिक्षक एक प्रकार का पुजारी होता है। एक शिक्षक की योग्यता और चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक प्रभावशाली छोटे बच्चों में कैरियर, चरित्र और नैतिक तंतुओं और शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए योग्यता को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता के बाद शिक्षक को गुरुदेवोभवः के रूप में पूजा जाता है। याचिकाकर्ता किस तरह का शिक्षक था या हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं सेवा में रहते हुए फर्जी डिग्री प्राप्त करने और साथ ही प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने में लिप्त था। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं और एक शिक्षक एक प्रकार का पुजारी होता है। एक शिक्षक की योग्यता और चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक प्रभावशाली छोटे बच्चों में कैरियर, चरित्र और नैतिक तंतुओं और शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए योग्यता को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता के बाद शिक्षक को गुरुदेवोभवः के रूप में पूजा जाता है। वह शिक्षा व्यवस्था का इंजन है। वह बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागृत करने में एक प्रमुख साधन है। उसके गुण ऐसे होने चाहिए जो कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें लाभ देने वाले को। **आदर्श शिक्षा महाविद्यालय बनाम सुभाष रहांगडाले (1)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

(पैरा 14)

वास्तव में, याचिकाकर्ता ने पहले ही फर्जी डिग्री के आधार पर प्रक्रियाओं में देरी का अनुचित लाभ उठाया था क्योंकि उसे मार्च, 2000 में पदोन्नत किया गया था और वह तब तक सेवा करता रहा जब तक कि उसे सेवा से बर्खास्त नहीं कर दिया गया।

(पैरा 15)

आगे निर्णीत किया, इस प्रकार के मामलों में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा उचित सजा नहीं हो सकती है क्योंकि कई मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर वह पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।

(पैरा 16)

आगे निर्णीत किया, आगे कहा गया कि ऊपर उल्लिखित कारणों से, मुझे वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(पैरा 17)

आरके मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ टीपी धुल, अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिये

राजेश बिंडल जे.

(1) हमारी संस्कृति में अनादि काल से शिक्षक सबसे सम्मानित व्यक्ति रहा है। उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है, जो निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट है:

> *"गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलकारं व्याप्त येन चराचरम् तत् पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः"*

अनुवाद करने पर इसका अर्थ है: गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु विष्णु हैं। गुरु ही शिव हैं। सच्चा गुरु सर्वोच्च निराकार ईश्वर है। मैं पवित्र गुरु के सामने साष्टांग प्रणाम करता हूं। असीम आकाश की अनंत छत्रछाया है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही सृष्टि में सर्वव्यापी है। मैं श्री गुरु को नमन करता हूं, जो हमें परम वास्तविकता बताते हैं।

(2) 5वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत कबीर ने निम्नलिखित दोहे में शिक्षक की स्तुति की:

> "*गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाय*।"

जब इसका अनुवाद किया जाता है तो इसका अर्थ होता है: मैं भगवान और अपने गुरु दोनों का सामना करता हूं। सबसे पहले मुझे किसे प्रणाम करना चाहिए? मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करता हूं क्योंकि उन्होंने ही मुझे दिखाया है ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग।

(3) इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षक था, को कुछ सेवा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी डिग्री प्राप्त करने का दोषी पाया गया था।

(4) याचिकाकर्ता, जो एसएस मास्टर के रूप में कार्यरत था, ने 9.5.2012 के आदेश (अनुलग्नक पी-3) को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था; आदेश दिनांक 23.8.2012 (अनुलग्नक पी-5), जिसके द्वारा उनके द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी और आदेश दिनांक 9.12.2014 (अनुलग्नक पी-10), जिसके द्वारा अपील में पारित आदेश के खिलाफ समीक्षा खारिज कर दी गई थी।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को एसएस मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और 8.11.1991 को उनकी सेवा में शामिल हुआ था। एक आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण उन्हें 17.1.2004 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 5/27.7.2005 को बहाल कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को आरोप पत्र जारी किया गया, जिस पर उसने जवाब दाखिल किया। पूछताछ के दौरान एमए की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप तो साबित हो गया, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि याचिकाकर्ता को उक्त फर्जी डिग्री के आधार पर कभी कोई लाभ मिला हो। जांच के बाद, याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए दिनांक 9.4.2012 को नोटिस जारी किया गया कि क्यों न सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी जाए, जिस पर याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया। आदेश दिनांक 9.5.2012 द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रथम अपील में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.8.2012 के आदेश द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया था। दिनांक 23.8.2012. के आदेश के विरुद्ध दायर दूसरी अपील आदेश दिनांक 9.4.2013. के तहत खारिज कर दी गई यह पता चलने पर कि एक अन्य शिक्षक, जिसे इसी तरह रखा गया था, को सेवा से समय-पूर्व सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी, याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.4.2014 को समीक्षा आवेदन दायर किया, जिस पर दिनांक 9.12.2014 के संचार के माध्यम से विचार नहीं किया गया।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सेवा से बर्खास्तगी के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि एक बार याचिकाकर्ता और दूसरे शिक्षक, जिन्होंने भी स्नातकोत्तर की फर्जी डिग्री प्राप्त की थी, को भी इसी तरह रखा गया था, तो पुरस्कार देने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था। सज़ा. याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि मनोहर लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता ने उक्त फर्जी डिग्री के आधार पर कभी कोई सेवा लाभ नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का सेवा से बर्खास्त होने तक का रिकॉर्ड बेदाग था। वास्तव में, उसके साथ धोखा हुआ क्योंकि उसे जारी किया गया प्रमाणपत्र, जो नकली पाया गया, उस परीक्षा से संबंधित नहीं था, जिसमें वह उपस्थित हुआ था।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(8) याचिकाकर्ता 8.11.1991 को एसएस मास्टर के रूप में सेवा में शामिल हुआ। पदोन्नति पाने के लिए एम.ए. की फर्जी डिग्री पेश करने से संबंधित एक आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण, उन्हें 17.1.2004 को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में बहाल कर दिया गया था। उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। आरोप पत्र का उत्तर संतोषजनक न पाते हुए दिनांक 11.5.2010 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप इस प्रकार थे:

"1. प्रभारी अपराध जांच विभाग अपराध शाखा हिसार द्वारा पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि उसने यूनिवर्सिटी झाँसी के साथ मिलीभगत करके एमए अंग्रेजी डिग्री/सर्टिफिकेट वर्ष 1998 में क्रमांक 89466 का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।

2. कि उसने इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 1999 में उचित माध्यम से हरियाणा शिक्षा विभाग में लेक्चरर अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति के लिए अपना मामला उपमंडल शिक्षा अधिकारी रेवाडी को भेजा था और जिसे केस संख्या ई-टी/99/94 के माध्यम से अग्रेषित किया गया था। दिनांक 15 फरवरी 1999 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रेवाडी ने इसे निदेशालय के आदेश संख्या 15/42-99 ई-4(2) दिनांक 15 द्वारा उचित माध्यम से पदोन्नति के लिए पत्र संख्या ई-टी/99/543 दिनांक 2 अप्रैल 1999 के माध्यम से निदेशालय को भेज दिया। मार्च 2000 में उन्हें अंग्रेजी व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में अंग्रेजी व्याख्याता का पद स्वीकार कर लिया।"

(9) दिनांक 28.2.2012 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए। जांच अधिकारी ने पाया कि हालांकि याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुआ। प्रस्तुत अंकपत्र/डिग्री फर्जी थी। याचिकाकर्ता ने एमए की फर्जी डिग्री के आधार पर अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में पदोन्नति के लिए अपना दावा पेश किया था। 15.3.2000 को पदोन्नति का आदेश भी पारित कर दिया गया। हालांकि, दावा है कि इसका वास्तविक लाभ नहीं उठाया गया. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा दायर जवाब पर विचार करने और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने राय दी कि याचिकाकर्ता ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी से अंग्रेजी में एमए की फर्जी डिग्री प्राप्त की और फर्जी डिग्री का लाभ उठाया। उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन किया और उन्हें पदोन्नति मिल गई। वे काफी समय तक व्याख्याता के रूप में कार्य करते रहे। सज़ा के आदेश दिनांक 9.5.2012 का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है:

"अब, फिर से, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले की जांच रिपोर्ट के पूरे रिकॉर्ड और श्री राधे श्याम के सभी अभ्यावेदनों को देखने के बाद, मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि श्री राधे श्याम को एमए के रोल नंबर 89466 वर्ष 1998 के तहत फर्जी प्रमाण पत्र/डिग्री मिली थी। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी से अंग्रेजी में स्नातक किया और फर्जी डिग्री का लाभ उठाया। उसने

लेक्चरर इंग्लिश के पद पर प्रमोशन के लिए आवेदन किया और उस फर्जी दस्तावेज के जरिए प्रमोशन पा लिया। उन्होंने फर्जी डिग्री के जरिए न सिर्फ प्रमोशन का लाभ लिया बल्कि लंबे समय तक लेक्चरर पद पर बने रहे। मैं विशेष रूप से शिक्षा विभाग में इस प्रकार के मामलों में नरम रुख अपनाने का इच्छुक नहीं हूं, जहां छात्रों को ईमानदारी और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाना मास्टर्स का प्राथमिक और नैतिक कर्तव्य है।"

(10) याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील दायर की। इसे 23 अगस्त 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह दर्ज किया गया है कि सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने सद्भावना से पदोन्नति के लिए आवेदन किया था और पदोन्नति का आदेश प्राप्त करने के बाद, लेक्चरर के पद पर ज्वाइन किया और सेवा देते रहे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दूसरी अपील दायर की। इसे भी 9 अप्रैल 2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अदालत द्वारा याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए एफआईआर में बरी करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

(11) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 30 अप्रैल 2014 को समीक्षा आवेदन दायर किया और दावा किया कि इसी तरह के पद पर तैनात मनोहर लाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा पर विचार किया जाना चाहिए था।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करते हुए, मुझे दी गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिली। हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 1987 (संक्षेप में, 'नियम') में निहित किसी भी प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है, जो किसी कर्मचारी को पारित आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने में सक्षम बनाता है। समीक्षा क़ानून का निर्माण है और स्वाभाविक रूप से किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है, इसलिए प्राधिकारी द्वारा इसका मनोरंजन न करना गलत नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का रुख कि एक कर्मचारी को एक स्मारक दायर करने का अधिकार दिया गया है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कारण से खारिज कर दिया जाना चाहिए कि दावे के समर्थन में कोई नियम या निर्देश नहीं हैं जैसा कि नियम 19(2) में परिकल्पित है।) उद्धृत किया गया है।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की यह दलील कि उसने फर्जी डिग्री का कोई लाभ नहीं उठाया, दंडात्मक और अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा गलत पाया गया। बल्कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर याचिकाकर्ता ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया, इसलिए यह कहना कि याचिकाकर्ता ने कभी भी फर्जी डिग्री का लाभ नहीं उठाया, पूरी तरह से गलत है।

(14) भले ही मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया हो, मेरी राय में, याचिकाकर्ता सेवा से बर्खास्तगी की सजा का हकदार है। वह एक शिक्षक थे, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श थे। यदि उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, जहां पदोन्नति पाने के लिए उसे फर्जी डिग्री पेश करने की अनुमति दी जा सकती है और पदोन्नति पाने के बाद उसे यह अनुरोध करने की अनुमति दी जाती है कि उसके प्रति उदारता दिखाई जाए, तो इससे सभी संबंधितों को गलत संकेत जाएगा। हमें बुराई को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में कर्मचारी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि अन्य सभी को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने से रोका जा सके। फर्जी डिग्री के आधार पर ऐसे व्यक्ति द्वारा निकाली गई अतिरिक्त राशि की वसूली भी ऐसे मामलों में अधिकारियों द्वारा जांच की जाने वाली बात है। याचिकाकर्ता किस तरह का शिक्षक था या हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं सेवा में रहते हुए फर्जी डिग्री प्राप्त करने और प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने में लिप्त था। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर हैं और शिक्षक एक प्रकार का पुजारी होता है। एक शिक्षक की योग्यता और चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक प्रभावशाली छोटे बच्चों में कैरियर, चरित्र और नैतिक तंतुओं और शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए योग्यता को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता के बाद शिक्षक को गुरुदेवोभवः के रूप में पूजा जाता है। वह शिक्षा व्यवस्था का इंजन है. वह बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागृत करने में एक प्रमुख साधन है। उसके गुण ऐसे होने चाहिए जो लाभकारी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। **आदर्श शिक्षा महाविद्यालय एवं अन्य बनाम सुभाष रहांगडाले एवं अन्य (2)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है।

(15) वास्तव में, याचिकाकर्ता पहले ही इसका अनुचित लाभ उठा चुका था फर्जी डिग्री के आधार पर उनकी पदोन्नति होने से प्रक्रियाओं में देरी हुई मार्च 2000 और तब तक सेवा करते रहे जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं कर दिया गया सेवा।

(16) इस प्रकार के मामलों में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा उचित सजा नहीं हो सकती है क्योंकि कई मामलों में, किसी कर्मचारी द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर, वह पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।

(17) ऊपर उल्लिखित कारणों से, मुझे वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं दिख रही है। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(18) आदेश से अलग होने से पहले यह अदालत अधिकारियों पर ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिए दबाव डालना चाहेगी, जहां शिक्षकों ने कोई लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी डिग्री पेश की थी, भले ही उन्होंने लाभ उठाया हो या नहीं, ताकि कोई भी फर्जी डिग्री प्राप्त करने के बारे में सोचने की हिम्मत न कर सके।

अस्वीकरण:

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा